विचार बिन्दु

धैर्य कड़ुवा होता है, पर उसका फल मीठा होता है। –रूसो

राजस्थान : श्री अन्न उत्पादन में सिरमौर - उज्ज्वल भविष्य

राजस्थान सहित भारत में मोटे अनाज, जिन्हें श्री अन्न के रूप में जाना जाता है, ने हाल के वर्षों में अपनी पोषण शक्ति, पर्यावरणीय स्थिरता और आर्थिक संभावनाओं के कारण वैश्विक और राष्ट्रीय स्तर पर ध्यान आकर्षित किया है। 2024-25 में भारत ने 180.15 लाख टन मिलेट का रिकॉर्ड उत्पादन किया, जो पिछले वर्ष की तुलना में 4.43 लाख टन अधिक है। इस उत्पादन में राजस्थान ने अग्रणी भूमिका निभाई, जिसने न केवल देश में बल्कि वैश्विक मिलेट उत्पादन में भी अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज की। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन (एफएओ) 2023 के अनुसार, भारत दुनिया का सबसे बड़ा मिलेट उत्पादक है, जो वैश्विक उत्पादन का 38.4% हिस्सा देता है। राजस्थान, अपनी अनुकूल जलवायु, मिट्टी और पारंपरिक खेती की प्रथाओं के साथ, इस क्षेत्र में अग्रणी बनकर उभरा है। राजस्थान में श्री अन्न के उत्पादन, इसके स्वास्थ्य लाभ, जैविक खेती, पर्यावरणीय अनुकूलता, पशु आहार में उपयोग, सामाजिक-आर्थिक प्रभाव, नवीन खाद्य उत्पादों, युवा पीढ़ी के उत्साह, सरकारी सहायता, कम लागत उत्पादन और निर्यात में अग्रणी इसे महत्वपूर्ण बनाते हैं। राजस्थान का मरुस्थलीय और अर्ध-शुष्क जलवायु मिलेट की खेती के लिए आदर्श है। बाजरा, मक्का, ज्वार और रागी जैसे मोटे अनाज इस क्षेत्र में सदियों से उगाए जाते रहे हैं, क्योंकि ये कम पानी और न्यूनतम उर्वरकों की आवश्यकता के साथ कठिन परिस्थितियों में पनप सकते हैं। बाजरा, जो राजस्थान में सबसे अधिक उत्पादित मिलेट है, न केवल स्थानीय आहार का हिस्सा है, बल्कि यह पशु आहार और जैविक खेती के लिए भी महत्वपूर्ण है। 2024-25 में राजस्थान ने देश के कुल मिलेट उत्पादन में सबसे बड़ा योगदान दिया, जिसमें बाजरा का हिस्सा सर्वाधिक रहा। यह उपलब्धि केवल उत्पादन तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके पीछे राज्य की पारंपरिक ज्ञान प्रणाली, किसानों की मेहनत और सरकार की नीतियों का समन्वय है।

मिलेट का सबसे बड़ा लाभ इसका पोषण मूल्य है। ये अनाज प्रोटीन, फाइबर, विटामिन (विशेष रूप से बी-कॉम्प्लेक्स) और खनिजों जैसे लोहा, कैल्शियम और मैग्नीशियम से भरपूर होते हैं। ग्लूटेन-मुक्त होने के कारण ये सीलिएक रोग से पीड़ित लोगों के लिए उपयुक्त हैं, और कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स के कारण मधुमेह रोगियों के लिए लाभकारी हैं। राजस्थान में, जहां कुपोषण एक गंभीर समस्या रही है, मिलेट ने स्थानीय आहार में पोषण की कमी को दूर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस-4, 2015-16) के अनुसार, राजस्थान में 5 वर्ष से कम आयु के 39.1% बच्चे कद में छोटे थे, और 46.8% महिलाएं एनीमिया से ग्रस्त थी। इस श्री अन्न ने अर्थात मिलेट, विशेष रूप से ज्वार, बाजरा और मक्का, आयरन और कैल्शियम की पूर्ति में सहायक हैं, जिससे कुपोषण और एनीमिया को कम करने में मदद मिलती है। राजस्थान सरकार ने आंगनवाड़ी केंद्रों और स्कूलों में मिलेट आधारित भोजन को शामिल किया है, जैसे बाजरे की खिचड़ी और रागी के लड्डू, जो बच्चों और गर्भवती महिलाओं के लिए पौष्टिक भोजन के रूप में परोसे जाते हैं।

मिलेट की खेती पर्यावरण के लिए भी अनुकूल है। ये फसलें कम पानी और उर्वरकों पर निर्भर होती हैं, जिससे यह रासायनिक खेती के पर्यावरणीय दुष्प्रभावों को कम करती हैं। राजस्थान में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कई पहल शुरू की हैं। 'राज किसान जैविक' मोबाइल ऐप, जैविक हाट (दुर्गापुरा, जयपुर), और जैविक आदान (ड्रम, बाल्टी, आदि) पर 50-75% सब्सिडी जैसी योजनाएं किसानों को प्रोत्साहित कर रही हैं। जैविक खेती न केवल मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखती है, बल्कि यह जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने में भी मदद करती है। मिलेट की फसलें सूखा-सहिष्णु होती हैं और उच्च तापमान में भी अच्छा प्रदर्शन करती हैं, जो राजस्थान जैसे शुष्क क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण है। प्राकृतिक खेती के तहत नीति आयोग की पहल में राजस्थान में 17,900 से अधिक किसानों को प्रशिक्षण दिया गया है, और 13,946 किसानों को जैविक खेती के लिए उपकरण प्रदान किए गए हैं।

मिलेट का उपयोग केवल मानव आहार तक सीमित नहीं है, यह पशु आहार के रूप में भी महत्वपूर्ण है। राजस्थान, जो देश में दुग्ध उत्पादन में दूसरे स्थान पर है, पशुपालन के लिए मिलेट के अवशेषों और चारे पर निर्भर करता है। मक्का,बाजरे और ज्वार के डंठल पशुओं के लिए पौष्टिक चारा प्रदान करते हैं, जिससे डेयरी उद्योग को बढ़ावा मिलता है। जैसलमेर जिले में प्रति व्यक्ति 1,085 ग्राम दूध की उपलब्धता इस बात का प्रमाण है कि पशुपालन और मिलेट उत्पादन का गहरा संबंध है। इसका सामाजिक आर्थिक विकास में भी योगदान है, क्योंकि पशुपालन ग्रामीण परिवारों, विशेष रूप से छोटे और सीमांत किसानों, के लिए आय का एक अतिरिक्त स्त्रोत है।

मिलेट का सबसे बड़ा लाभ इसका पोषण मूल्य है। ये अनाज प्रोटीन, फाइबर, विटामिन (विशेष रूप से बी-कॉम्प्लेक्स) और खनिजों जैसे लोहा, कैल्शियम और मैग्नीशियम से भरपूर होते हैं। ग्लूटेन-मुक्त होने के कारण ये सीलिएक रोग से पीड़ित लोगों के लिए उपयुक्त हैं, और कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स के कारण मधुमेह रोगियों के लिए लाभकारी हैं।

मिलेट का आर्थिक प्रभाव राजस्थान में गहरा है। यह छोटे और सीमांत किसानों के लिए कम लागत में खेती का एक व्यवहार्य विकल्प है। इस पारंपरिक खेती में लागत कम होती है, क्योंकि यह रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों पर कम निर्भर होती है। कृषि मशीनरी सब्सिडी योजनाओं, जैसे राष्ट्रीय कृषि विकास योजना और कृषि मशीनीकरण उप-मिशन (एसएमएएम), ने किसानों को कम लागत में उत्पादन बढ़ाने में मदद की है। इसके अलावा, मिलेट आधारित उत्पादों की बढ़ती मांग ने ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा किए हैं। विशेष रूप से, महिला स्वयं सहायता समूहों और फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गनाइजेशन (एफपीओ) को मिलेट प्रसंस्करण और विपणन में शामिल किया गया है, जिससे उनकी आय में वृद्धि हुई है।

मिलेट आधारित नवीन खाद्य पदार्थों ने राजस्थान में खाद्य उद्योग को नई दिशा दी है। बाजरे के बिस्किट, रागी के नूडल्स, मक्का और ज्वार की खिचड़ी, और मिलेट आधारित स्नैक्स जैसे उत्पादों ने शहरी और ग्रामीण दोनों बाजारों में लोकप्रियता हासिल की है। स्टार्टअप्स और छोटे उद्यमियों ने मिलेट को आधुनिक उपभोक्ताओं की जरूरतों के अनुसार पुनर्जनन किया है। उदाहरण के लिए, जयपुर और उदयपुर जैसे शहरों में मिलेट कैफे और रेस्तरां खुल रहे हैं, जो पारंपरिक और आधुनिक व्यंजनों का मिश्रण पेश करते हैं। यह नवाचार न केवल खाद्य संस्कृति को समृद्ध कर रहा है, बल्कि स्थानीय किसानों को भी बाजार से जोड़ रहा है।

युवा पीढ़ी में मिलेट को लेकर उत्साह बढ़ रहा है। सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से, युवा उद्यमी और किसान मिलेट के लाभों को बढ़ावा दे रहे हैं। 'मिलेट एक्सपीरियंस सेंटर' जैसे पहल, जो दिल्ली हाट में स्थापित किया गया है, ने राजस्थान के युवाओं को प्रेरित किया है कि वे मिलेट आधारित व्यवसाय शुरू करें। इसके अलावा, सरकार द्वारा संचालित प्रशिक्षण कार्यक्रम और एफपीओ गठन ने युवा किसानों को मिलेट की खेती और विपणन में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया है। राजस्थान के विश्वविद्यालयों और कृषि संस्थानों में मिलेट पर अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए विशेष पाठ्यक्रम शुरू किए गए हैं। केंद्र और राज्य सरकारों की सहायता ने मिलेट उत्पादन को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफएसएम) और पीएम-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) के तहत राजस्थान में मिलेट की खेती के लिए 8,000 करोड़ का आवंटन किया गया है। इसके अतिरिक्त, पीएम-एफएमई योजना के तहत 2,000 करोड़ और उत्पाद-लिंक्ड प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना के तहत 800 करोड़ का निवेश मिलेट प्रसंस्करण और मूल्यवर्धन के लिए किया गया है। राजस्थान सरकार ने अलग से कृषि बजट पेश किया है, जिसमें मिलेट उत्पादन और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रावधान हैं। 'राज किसान जैविक' ऐप जैसे डिजिटल उपकरणों ने किसानों को जैविक मिलेट के क्रेता-विक्रेता से जोड़ा है, जिससे उनकी पहुंच वैश्विक बाजार तक बढ़ी है। मोटे अनाज के निर्यात के क्षेत्र में राजस्थान ने उल्लेखनीय प्रगति की है। 2024-25 में भारत ने 89,164.96 टन मिलेट का निर्यात किया, जिसमें राजस्थान का योगदान प्रमुख रहा मक्का,बाजरा, ज्वार और रागी जैसे मिलेट की मांग मध्य पूर्व, यूरोप और उत्तरी अमेरिका में बढ़ रही है। एपीडा के नेतृत्व में निर्यात संवर्धन मंच और मिलेट निर्यातक पोर्टल ने राजस्थानी किसानों को वैश्विक बाजार से जोड़ा है। निर्यात से होने वाली आय ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत किया है और किसानों की आय में 20-30% की वृद्धि दर्ज की गई है।

हालांकि, मिलेट उत्पादन और विपणन में कई चुनौतियां भी हैं। पहली चुनौती है जागरूकता की कमी। शहरी उपभोक्ताओं में मिलेट के पोषण लाभों के बारे में जानकारी का अभाव है, जिसके कारण इसकी मांग अभी भी सीमित है। दूसरी चुनौती है प्रसंस्करण और भंडारण की कमी। मिलेट की शेल्फ लाइफ को बढ़ाने और गुणवत्ता बनाए रखने के लिए आधुनिक तकनीकों की आवश्यकता है। तीसरी चुनौती है वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धा। अन्य देश, जैसे अफ्रीकी राष्ट्र, भी मिलेट निर्यात में सक्रिय हैं, जिससे भारत को गुणवत्ता और कीमत में प्रतिस्पर्धा करनी पड़ रही है। इसके अलावा, छोटे और सीमांत किसानों के लिए उच्च उपज वाली किस्मों और आधुनिक उपकरणों तक पहुंच सीमित है, जिसे दूर करने के लिए और अधिक निवेश की आवश्यकता है।

इन चुनौतियों के बावजूद, राजस्थान में मिलेट का भविष्य उज्ज्वल है। सरकार, किसान, और निजी क्षेत्र के संयुक्त प्रयासों ने श्री अन्न को एक टिकाऊ और लाभकारी फसल के रूप में स्थापित किया है। मिलेट न केवल पोषण और स्वास्थ्य का आधार है, बल्कि यह पर्यावरणीय स्थिरता, सामाजिक-आर्थिक विकास, और वैश्विक बाजार में भारत की स्थिति को मजबूत करने का एक सशक्त माध्यम भी है। राजस्थान, अपनी पारंपरिक खेती की विरासत और आधुनिक नवाचारों के साथ, इस क्षेत्र में नेतृत्व करने के लिए तैयार है। केंद्र और राज्य सरकारों की नीतियां, युवा पीढ़ी का उत्साह, और वैश्विक मांग का बढ़ता रुझान मिलकर श्री अन्न को एक नई पहचान दे रहे हैं, जो न केवल राजस्थान बल्कि पूरे भारत के लिए गर्व का विषय है।

–अतिथि सम्पादक,
राजेन्द्र मोहन शर्मा
वरिष्ठ साहित्यकार, शिक्षाविद् और चिन्तक

अलबेला मुल्क हमारा

महावीर सिंह

शहरों में बहुत सी पॉपुलर चाय, पान की दुकानें, थड़िया, प्रातः टहलने वालों के समूह, गांवों में पीपल - बड़ के गट्टों पर बैठे ताशपत्ती खेलने वालों के समूह देश-विदेश के ज्वलंत मुद्दों पर चर्चा करते मिल जाएंगे। ऐसे मुद्दों पर लोगों की राय जानने के बेहतरीन अवसर प्रदान करते है। इन्हीं समूहों में चली चर्चाओं, बहसों के कुछ अंश इस लेख में दिए जा रहे है::--

आजकल आए दिन कोई न कोई बाबा, मौलवी, धर्माधिकारी, कथावाचक, --- बहन, बेटियों, बीवियों के पहनावे, चरित्र पर तरह-तरह से ज्ञानवृद्धि कर रहे है। ऐसी ऐसी बातें कहीं है जिन्हें यहां लिखना पढने वालों की तोहीन होगी। इन कथावाचकों, मौलवियों, तरह-तरह के सिद्ध आचार्यों आदि की जबान को आशाराम, राम रहीम और न जाने ऐसे कितनो के खिलाफ एक शब्द बोलने से पहले लकवा क्यों मार जाता है? इन आशा रामों, राम रहीमों को कितनी आसानी से जमानत, दर्जनों बार पैरोल मिल जाता है!!!??? एक आदमी को तो, चुनाव आए नहीं, उसका जन्मदिन आया नहीं, झट पैरोल मिल जाती है। क्या जबरदस्त सेटिंग-वेटिंग है सेटिंग की सरकारों से।

क्या इन्होंने जो बहुचर्चित कारनामें किए है, उनमें, इन सत्ता में बैठे बड़े लोगों की भी किसी किसी प्रकार से भागीदारी होती है क्या? यह आम आदमी पूछता रहता है। हम हिन्दू भाई मंदिर में भी बाहुबल दिखाने से नहीं चूकते। किसी वार-त्योंहार पर मंदिर जाए। बिना धक्का-मुक्की के दर्शन कर लें तो ही समझो कि, शायद, भगवान जी आप पर बहुत ही मेहरबान है। भगवान के दर्शन के लिए इतनी धक्कम-धक्की, लगता है, हम हिन्दुओं का इस काम पर एकाधिकार है। एक सज्जन का कहना था कि इतनी कठिनाइयों के बीच जो श्रद्धालु दर्शन किए बिना नहीं जाते तो भगवान जी का कोमल हृदय तो उन पर पिघलेगा, आशीर्वाद, मनचाहा वरदान देगा ही। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय दुर्गा मैया। क्रम लिखने में कोई प्रोटोकॉल संबंधी गलती हो तो इस नादान को माफ करते हुए, आप ही, शांति से, सुधार कर लेना।

वैसे यों ही, चलते-चलते एक बात कह दी किसी ने की चर्चों, मस्जिदों में, गुरुद्वारों में दर्शनों के लिए इतनी धक्का-मुक्की क्यों नहीं होती??? कुछ सूरमा आए दिन फतवा जारी करते रहते है कि कब-कब क्या क्या नहीं खाना। इस बार किसी बड़े सूबे की सरकार ने उनकी बात सुन ली। एक पुराना, विस्मृत आदेश निकाल कर फतवा जारी कर ही दिया कि 15 अगस्त, आजादी के दिन मांस-मच्छी सेवन निषेद्य। आजादी के दिन खाने-पीने की आजादी खत्म। कर लो क्या करोगे?

न्यायालयों के भी कुछ फैसले जन चर्चा के मुद्दे बनते ही रहते है। कबूतर खाने कहां होंगे या नहीं होंगे और होंगे तो कहां-कहां? इसका फैसला भी उच्च या उच्चतम न्यायालय ही करे और वह भी धार्मिक और पक्षी प्रेमी संगठनों से पूछ के करे? तो फिर यह नगर निगम या उनसे उपर बैठी सरकार क्या करती है? चर्चाओं में सुन -- करते है न, विज्ञापनों के माध्यम से नेताओं के चिकने-चुपड़े चेहरों को बड़े अखबारों, टीवी चैनल्स पर दिखाना और उनके द्वारा स्वर्ग जैसा हिंदुस्तान बना देने की शेखी बघारने को सुनाते रहना।

दिल्ली में कुत्तों के संबंध में भी कोई निर्णय हुआ। इन्हें शेल्टर होम भेजने के निर्देश दे दिया, सुप्रीम कोर्ट ने और पशु प्रेमी, राजनेता लोग हो गए आक्रोशित, आंदोलित?? वैसे, अगर, सड़कों पर लोग कुत्ता प्रेम दिखाते हुए, बिस्किट्स खिलाते हुए दिखें और दूसरा कोई ऑब्जेक्शन करे तो उसे क्या सुनना पड़ सकता है, कोई अंदाज है--- सबसे कॉमन है,अबे चल अपना काम कर, खुद नहीं कर सकता तो दूसरों को तो करने दे, इन निरहि प्राणियों की सेवा---। वैसे कुत्ते भी फाइव स्टार फूड के अभ्यस्त हो गए, ऐसे वैसी बिस्किट्स, पुरानी बासी रोटी - सब्जी आदि की तरफ आंख भी नहीं उठते!!! फैसले का विरोध करने वालों के खिलाफ, अवमानना की कार्यवाही होगी क्या? खबर तो छापी है, होगी या पर क्या पता, नहीं भी हो ??? आदेश तो है, किसी इलाके में आवारा कुत्ता घूमता हुआ नहीं दिखना चाहिए --(आंकड़ों पर नजर डालें, बड़े भयावह है -- 2024 में 37 लाख से ज्यादा डॉग बाइट, 54 लोगों की डैथ, रोजाना 10 हजार से अधिक काटने के केसेज!!!!) फिर भी स्थानीय, प्रदेशीय और केंद्रीय सरकारी नहीं जागें तो क्या करेगा कोर्ट, फिर चाहे वह छोटा हो, बड़ा हो, क्या फर्क पड़ता है?

इतिहास से गड़े मुद्दे निकाल कर लड़ना, हमारा पसंदीदा खेल है। कई बोलने वाले शूरवीर अखंड भारत की सीमाओं के अनुसार अखंड देश बनाने के जोशीले भाषण हमेशा देते रहते है। कौन सा अखंड भारत कौन सी सीमाएं यह मत पुछ लेना। ज्यादा कोई पूछे तो अखंड भारत माता का एक कालजई चित्र है, राजा रवि वर्मा का उसकी सीमाएं बता देते है। इस से गहरे इतिहास ज्ञान की न उनको जरूरत और न उनके तय श्रोताओं को। भूतकाल पर गर्व करते रहना - उस में ही आत्म मुग्ध रहना हमें स्वर्ग में रहने जैसा सुख देता है। भूत कल में हम परमाणु बम, सबसे आधुनिक मिसाइल, इनफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में, रोबोट, आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस, मानव रोग निदान के वर्तमान में ज्ञात सारे उपचार - सर्जरी का जाएं प्राप्त कर चुके थे आदि आदि। अत्याधुनिक हथियार बनाना हमारे पूर्वजों का बांए हाथ का खेल था। यह जो ब्रह्मोस, तेजस, अग्नि आदि पर जो गर्व करते है न, वो सब पहले से ही हमारे, देव रचित धर्म शास्त्रों में वर्णित है। थे। कुछ अक्ल के दुश्मन पूछ लेते है, फिर ऐसा क्या हुआ कि इन सिकंदर, हूण, कुषाण, शक, मुसलमान, मुगल, अंग्रेज - आदि ने हमारे अखंड भारत की सीमाएं पार कैसे की???

एक तो ऐसे शूरवीर हैं जो अब भी,आजादी के 78 साल बाद भी यह कहते नहीं अघाते कि गुलामी के सारे अंश मिटा कर मानेंगे। एक ने धीरे से पूछा कितनी कब्रें ओर खोदनी है, कितने मस्जिद, चर्च आदि ढहाने हैं। कइयों को इनके नीचे भी मंदिरों के होने के सपने तो आते रहते हैं!!! वैसे हमारा इतिहास इस प्रकार के मुद्दों से भरा पड़ा है। सदियों तक, नेताओं, तथाकथित सांस्कृतिक संगठनों को मसाला - काम मिल सकता है -- खोदा खादी, तोड़ने-फोड़ने के लिए। वैसे शुक्र है अभी अंग्रेजों की बनाई इमारतों, चर्चों, शिक्षण व चिकित्सा संस्थानो पर इन शूरवीरों की नजर नहीं पड़ी। वैसे वर्तमान में इतिहास पुनर्लेखन, संस्कृतिकरण कार्य द्रुत गति से चल रहा है। जल्दी ही विदेशियों के पिछलगुओं द्वारा लिखे इतिहास से मुक्ति मिल जाएगी। हल्दीघाटी युद्ध में महाराणा प्रताप को विजयी घोषित करने में कोई दिक्कत नहीं। खानवा युद्ध में भी बाबर की विजय के स्थान, कम से कम, युद्ध को अनिर्णीत तो दिखाया ही जा सकता है। इब्राहिम को, इस युद्ध के अनिर्णय का दोषी तो ठहराया ही जा सकता है। इसी प्रकार से दूसरे तथ्यों का शुद्धिकरण कर, गलत तथ्यों को हटा दिया जाएगा। सभी मंत्री, सहलाकर, अहलाकर लोग रात ओर दिन इस राष्ट्र उत्थान कार्य में लगे हुए है। भारत विभाजन का एक नया नैरेटिव उछला है। वह जो राजा रवि वर्मा के चित्र में अखंड भारत की सीमाएं है, उन्हें किसने भंग की ---- कुछ कहते हैं कांग्रेस, माउंटबेटन से मिल कर नेहरू और जिन्ना ने यह किया, कुछ का कहना है वीर सावरकर, हिंदू महा सभा, जिन्ना ने यह किया। आने वाले दिनों में सड़कों पर इसका भी फैसला हो ही जाएगा। वैसे कई इतिहासकारों का मानना है कि भारत विभाजन के लिए ब्रिटिश सरकार, जिन्ना व हिन्दू महासभा, मुख्य रूप से जिम्मेदार थे। ऐतिहासिक व भौगोलिक दृष्टि से यह, उस समय की, धरातलीय सच्चाई का मूर्त रूप था।

ऐसे समूहों में संविधान पर बात न हो ऐसा हो नहीं सकता। देखते ही देखते, इत्मीनान से चाय की चुस्कियां लेने वाले दो समूहों में बंट गए। एक का कहना था भारत का संविधान में किसान, मजदूर, व्यापारी, व्यवसाई, एस सी, एस टी, ओबीसी,सभी भाषा बोलने वालों, सब को उन्नति के अवसर देता है। सभी धर्मों का बराबर सम्मान करता है, राज कार्य में धर्म आधार पर निर्णय नहीं होकर संविधान के अनुसार कम होता है। एक व्यक्ति एक मत,अब को समान अधिकार। कानून अब के लिए बराबर। दूसरे पक्ष का कहना था कि इसमें भारतीय समाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, शास्त्रीय मूल्यों का सर्वथा अभाव, पूर्णतः भारतीयता विहीन।

जन्म कुंडली देख कर इलाज का पवित्र कार्य तो वर्षों पहले से चल रहा है। अब तो अपराधियों की जन्म से, उनकी पूरी अपराध कुंडली खुल जाएगी और भविष्य में उनको क्या क्या अपराध करने हैं इन सब बातों का पता चल जाएगा। समाज पूर्णतः अपराध मुक्त!! जो काम भगवान श्री राम, श्री कृष्ण भी लाख कोशिश करके नहीं कर पाए, वो अब होगा। फिर इतनी पुलिस की क्या जरूरत रह जाएगी??

जन्माष्टमी का शुभ दिन था। एक प्रातः भ्रमणकारी भाई ने दूसरे से कहा, जय श्री कृष्ण --- दूसरे ने बुलंद आवाज में कहा, जय जय श्री राम बोलो पहले फिर जय कृष्ण। तीसरा दूर से ही बोला श्रीराम, श्रीकृष्ण दोनों गंगा मैया की देन है और गंगा मैया को धरती पर लाए जय बम भोले, सो, सबसे पहले बोलो जय श्री बंब भोले, जय श्री बंब भोले। अब चल पड़ी बहस, आधे घंटे चली। बीच में एक बंगाली बाबू भी कूदे। सब की मैया जय काली मैया, डुबो दे दुश्मन की नैया। मैया नहीं तो कोई नहीं, सबसे बड़ी है मैया।

जन्माष्टमी पर गौ माता के बारे में बात न हो तो, ठीक नहीं। कुछ सिरफिरे पूछते है कि यह गोरक्षक छोटे मोटे व्यापारी,चरवाहों पर शौर्य प्रदर्शन करते है, क्यों नहीं बूचड़खानों पर धावा बोल, एक झटके में पूरा कर देते यह रोज रोज का झंझट। वैसे एक आदमी में बताया कि गौरक्षकों की चौकियां बनी हुई है, एक से आगे दूसरे को सूचना पहुंचती है । कहां कितनी चुंगी दे दी,कितनी बाकी, इसका ब्यौरा भी होता है। झगड़ा होता है चुंगी के न देने पर वरना सारा काम 100 प्रतिशत ईमानदारी का है। वैसे सदियों से चलते आ रहे प्रसिद्ध परबतसर मेले में भी इन शूरवीरों ने खूब काम किया है। धीरे-धीरे बंद कराके ही मानेंगे।

पशु पालकों को जरूर नुकसान होगा, सो उन्हें अभी से मांग उठा देनी चाहिए, नुकसान भरपाई की --- पशु पालक सम्मान निधि की।

आजकल स्वदेशी, आत्म निर्भर भारत पर चर्चा जोरों पर है। पाठकों को स्मरण होगा, त्यौहारों के अवसर पर, व्यापारी संगठन बड़े जोर-शोर से विदेशी उत्पादों का बहिष्कार। व देशी उत्पादों की खरीदी का आव्हान किया जाता है। बात बहुत छोटी सी है, कहो सरकार से कि उनकी लिस्ट के अनुसार उत्पादों का आयात पूर्णतः बंद करे।

लेकिन कुछ सोसल मीडिया शुरवीर व संगठन आव्हान कर रहे है कि किसी विदेशी ब्रांड उत्पादन की खरीदी नहीं करे। शायद सारे विदेशी ब्रांड वाले अधिकांश उत्पादों का उत्पादन भारत में, भारतीयों द्वारा किया जाता है। फिर इन कारखानों, श्रमिकों का क्या होगा?? एक फक्कड़ से आदमी ने यों ही एक प्रश्न उछल दिया -- हर दृष्टि से पूर्णतः 100 स्वदेशी करना तो सरकार के हाथ की बात है। विदेश से 0 प्रतिशत आयात, 100 प्रतिशत निर्यात, कोई सच्चा भारतीय विदेशी नागरिक नहीं बनेगा और जो बन गए उन्हें ले जाए गए मल असबाब सहित वापिस आने का हुक्म दो, विदेशों में पढाई बंद, जो पढ रहे है उन्हें वापिस बुलाओ। उसका कहना है, यह कर के देखो और फिर देखना भारत भी, इस अमृत काल में, भूतकाल वाली सी सोने की चिड़िया न बन जाए तो, मात्र 5,10 साल में और 100३, शर्तिया 2047 से पहले।

एक ने धीरे से पूछा, यह जो लोग विदेशों में है, वे लोग देश आकर करेंगे क्या?? दूसरे ने भी उतने ही धीमे स्वर में कहा देख, कोई गरीब मजदूर तो वहां हैं नहीं, सब बड़े आदमी या उनके बच्चे है। चिंता मत कर। व्यवसाई आकर व्यवसाय करेंगे, उद्यमी कोई कल कारखाना लगा लेंगे, जिनमें बाकी को नौकरी मिल जाएगी। ओर जो नेताओं के लड़के-लड़कियां है वे मां-बाप की राजनीति में सहयोग देंगे। यह धंधा खूब फले - फूलेगा जब तक 80३ भारतीयों को मुफ्त राशन व दूसरी सो कॉल्ड फ्रीबीज मिलती रहेंगी -- अमर रहे लोकतंत्र हमारा, एक वोट का समान अधिकार सबको -ओर बाकी कोई लोड नहीं, सब चंगा सी।

–महावीर सिंह, पूर्व आई एस

विशेष गहन पुनरीक्षण : जनता की सेवा में

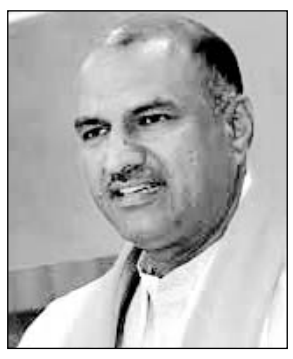

सी.पी. जोशी

भारत जैसे विशाल और विविधतापूर्ण लोकतंत्र में चुनावों को लेकर विवाद होना स्वाभाविक है, लेकिन ये विवाद लोकतंत्र को कमजोर नहीं करते, बल्कि उसकी जीवंतता को और मज़बूत करते हैं। यह साबित करते हैं कि पारदर्शिता और निष्पक्षता लगातार परखी और सुरक्षित की जा रही है। इस जीवंतता को बनाए रखने के लिए संवैधानिक संस्थाओं को समय-समय पर नये कदम उठाने और नवाचार करने की आवश्यकता होती है। हाल ही में चुनाव आयोग (ईसीआई) द्वारा शुरू की गई विशेष गहन पुनरीक्षण ऐसी ही एक पहल है।

24 जून 2025 को चुनाव आयोग ने बिहार विधानसभा चुनावों से पहले पूरे राज्य में विशेष गहन पुनरीक्षण कराने के दिशा-निर्देश जारी किए। आयोग ने संविधान के अनुच्छेद 324 और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 21 के तहत अपने अधिकारों का उपयोग करते हुए यह सुनिश्चित करने की पहल की कि मतदाता सूची में केवल वैध मतदाता ही शामिल हों।

यह कदम इस बात को दर्शाता है कि चुनाव आयोग एक पूर्णतः स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है, जो सरकार से पूरी तरह अलग होकर कार्य करती है। इस कदम की आवश्यकता लंबे समय से महसूस की जा रही थी। पिछले वर्षों में बार-बार ऐसी रिपोर्ट सामने आई हैं कि अवैध प्रवासी और अयोग्य लोग मतदाता सूची में शामिल हो रहे हैं। यह न केवल चुनावों की पवित्रता को कमजोर करता है बल्कि कई महत्त्वपूर्ण राज्यों में जनसांख्यिकी और सामाजिक-आर्थिक संतुलन को भी प्रभावित करता है। इस कारण मात्र एक नौकरशाही प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह निष्पक्षता और जन विश्वास बहाल करने का एक आवश्यक सुधारात्मक कदम है। विशेषकर बिहार जैसे राज्य के लिए, जहां पिछली बार ऐसा बड़ा संशोधन 2003 में हुआ था, यह अद्यतन काफी देर से हो रहा है।

यह रेखांकित करना भी आवश्यक है कि इस संबंध में आयोग के फैसलों की कोई जिम्मेदारी केंद्र सरकार पर नहीं आती। विपक्ष द्वारा बार-बार केंद्र और आयोग के निर्णयों को जोड़कर देखने की कोशिश संविधान की संरचना के विपरीत है। चुनाव आयोग न तो संसद के प्रति और न ही कार्यपालिका के प्रति अपने रोज़मर्रा के निर्णयों में जवाबदेह है। इसके फैसलों को केवल न्यायपालिका के समक्ष, चुनाव याचिका या संविधान के अनुच्छेद 32 और 226 के अंतर्गत दायर रिट द्वारा ही चुनौती दी जा सकती है। यही स्वतंत्रता आयोग की विश्वसनीयता सुनिश्चित करती है और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को राजनीतिक हस्तक्षेप से बचाती है।

एक व्यापक संदेश भी देता है- कि बदलती वास्तविकताओं के अनुसार निरंतर चुनावी सुधार आवश्यक हैं। जैसे-जैसे तकनीक बदल रही है और प्रवासन के पैटर्न बदल रहे हैं, मतदाता सूचियों को भी इनके अनुसार अद्यतन किया जाना चाहिए। साथ ही आयोग को दो महत्त्वपूर्ण जिम्मेदारियों में संतुलन बनाए रखना होगा-एक ओर नागरिकों के मतदान अधिकार की रक्षा और दूसरी ओर व्यवस्था में मौजूद खामियों और अवैधताओं को दूर करना। हर नाम को हटाना या बनाए रखना, नागरिकों के लोकतंत्र पर विश्वास को सीधे प्रभावित करता है।

1950 से ही चुनाव आयोग भारत की सबसे विश्वसनीय संस्थाओं में से एक रहा है। बिहार में इस लंबे समय से लंबित सुधार को लागू करके आयोग ने साफ, पारदर्शी और निष्पक्ष चुनावों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को पुनः स्थापित किया है। चुनौतियाँ आना स्वाभाविक हैं, लेकिन इन्हें लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा मानना चाहिए, न कि बाधा।

केवल एक प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं है, यह भारत की लोकतांत्रिक आत्मा का पुनः उद्घोष है। पुरानी और त्रुटिपूर्ण मतदाता सूचियों को दुरुस्त कर आयोग ने चुनावी वैधता की नींव को और मजबूत किया है। और स्वतंत्र रूप से ऐसा करके, आयोग ने यह सिद्धांत फिर से स्थापित किया है कि विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में मत की पवित्रता सर्वोपरि है।

सी.पी. जोशी
लोकसभा सांसद।

मसूदा-देवमाली सड़क मार्ग गड्ढ़ों से हो रहे हैं हादसे

- **30 अगस्त को देवमाली में ऐतिहासिक मेला भरने जा रहा है, इस मार्ग पर रोजाना हजारों श्रद्धालु पैदल आते हैं**
- **इस सड़क मार्ग पर 24 घंटे लोगों का आना-जाना रहता है**

मसूदा, (निसं)। मसूदा देवमाली सड़क मार्ग रामगढ़ चौराहे सेरेबारियों की ढाणी के निकट जगह जगह गहरे गड्ढ़े होने के कारण आए दिन सड़क हादसे हो रहे हैं।

इस मार्ग से गुजरने वाले ग्रामीण एवं वर्तमान में भगवान देवनारायण मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। सैकड़ों यात्रियों का पैदल जत्था मुख्य सड़क मार्ग के बीच में गहरे गड्ढे से वाहनों से गुजरते हैं। ग्राम पंचायत देवमाली में हर वर्ष भरने वाला इस वर्ष 29 व 30 अगस्त को ऐतिहासिक महत्व रखने वाले भगवान देवनारायण मेले में हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं की आवाजाही रहेगी, लेकिन मेले को लेकर प्रशासन सचेत नजर नहीं आ रहा है। इस सड़क मार्ग पर 24 घंटे लोगों का आना-जाना रहता है।

अचानक गड्ढा दिखाई देने पर वाहन चालक बचने का प्रयास करते हैं ऐसे में आए दिन दुर्घटनाएं हो रही है। यह रोड मसूदा नगर पालिका के अधीन आने के बावजूद स्थानीय प्रशासन एवं स्थानीय नेताओं की नींद नहीं खुल रही है।

जबकि इस मार्ग से कई स्थानी